602. SHRI C.O. POULOSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the reasons for the failure of nation's planning that after 50 years of Independence the problem of safe drinking water, elementary education, health, poverty eradication etc. are not solved;

(b) whether Government are considering to take the above problems far more seriously;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) In the last fifty years, there has been considerable improvement in all the sectors, even though the spread of benefits has been constrained by a faster growing population. The incidence of rural poverty has declined from 56% in 1973-74 to 37 per cent in 1993-94 as per the official estimates of poverty. Near self sufficiency in food production has been achieved. The literacy rate has increased from 18.33% in 1950-51 to 52.2% in 1990-91. The Crude Death Rate (CDR) has declined from 25.1 in 1951 to 8.9 in 1996, Infant Mortality Rate (IMR) has declined from 146 in 1951 to 72 in 1996, life expectancy rose from 32 years in 1947 to 61.1 years in 1991-96, National programmes for combating major public health problems were evolved and implemented.

(b) to (d) Poverty alleviation and improvement of basic amenities received special attention in Plants. In 1996, the Basic Minimum Services (BMS) Programme was launched for attainment of certain objectives within a specified time frame in seven specified areas including safe drinking water and health services. During the current year, Planning Commission has prepared Special Action Plans (SAPs) to be given emphasis in the Ninth Five Year Plan in five areas viz. (i) Food and Agriculture; (ii) Physical Infrastructure; (iii) Health, Education, Housing and Drinking Water; (iv) Information Technology; and (v) Water Resources Policy. Well-specified targets with fixed time-frames have been laid down for these sectors.

उत्तरांचल को विशेष सहायता

603. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरांचल को विशेष सहायता प्रदान करती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि उत्तरांचल का क्षेत्र और जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के बराबर है फिर भी वर्ष 1977-78 की तुलना में यह राशि निरन्तर घटती जा रही है और यह पिछले तीन वर्षों से 225 करोड़ रुपए पर स्थिर है; और

(ग) क्या सरकार इस धनराशि को हिमाचल प्रदेश के बराबर करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश के नामित पहाड़ी जिलों के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) दी जाती है जबकि हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है और इसे केन्द्रीय सहायता के वितरण में उपयुक्त महत्व दिया जाता है। अतः, संशोधित गाडगिल फार्मूला, 1991 के अंतर्गत उत्तरांचल के लिए एचएडीपी के अंतर्गत एससीए तथा हिमाचल प्रदेश को दी गई सामान्य केन्द्रीय सहायता तुलनीय नहीं है और इन्हें बराबर नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सहायता में वृद्धि करने के विगत में प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान एचएडीपी के